बिग बैंग घोषणाएं नहीं, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताता है बजट

सफाई पूरी, अब अर्थव्यवस्था के विस्तार का समय

▪ राजीव चंद्रशेखर
राज्यसभा सदस्य, भाजपा

पांच साल के आर्थिक विस्तार के बाद पिछली कुछ तिमाहियों में विकास दर धीमी हो गई है। इसके बावजूद पिछले एक दशक में किसी भी समय की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी रही है। इसे दोहराने वालों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रमुख भी हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी को अस्थायी करार दिया है। बजट 20-21 का कोई भी विश्लेषण 2014 के उन काले दिनों से लेकर पिछले छह वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सावधानी से अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण से शुरू होना चाहिए। मैं इसे मोदीनोमिक्स 1.0 कहता हूं।

मोदीनोमिक्स 1.0 की शुरुआत 16 तिमाही तक लगातार बढ़ी महंगाई, बिखरी वित्त व्यवस्था, चालू खाते के गंभीर संकट, भारी एनपीए से टूटे बैंकिंग सेक्टर, छद्म पूंजीवाद, घोटाले दर घोटाले से न्यूनतम स्तर पर पहुंचे निवेशकों के भरोसे, भ्रष्टाचार वाली सब्सिडी व्यवस्था, कमजोर राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार व नागरिकों के बीच विश्वास की कमी से शुरू हुई। छह वर्षों में मोदीनोमिक्स को इससे जूझना पड़ा, साथ ही ग्रोथ व विस्तार भी देना पड़ा। अर्थव्यवस्था को जहरमुक्त करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी, दिवालिया कानून, रेरा, नोटबंदी जैसे अनेक उपायों के साथ सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों में सुधार लागू किए। इसकी वजह से कांग्रेस द्वारा उपहार में दिया गया एनपीए सितंबर 2019 तक 9.03 फीसदी ही रह गया है। 2013-14 में जो महंगाई दर 9.3 फीसदी थी, वह 2019-20 में 30 सितंबर तक 3.3 फीसदी थी। चालू खाते का घाटा अब तक के न्यूनतम 1.5 फीसदी पर था। विदेशी मुद्रा का भंडार अब तक का सर्वाधिक 460 अरब डॉलर हो गया है। 2013-14 में निवेशक भारत से भाग रहे थे, जबकि 2019 में भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग को 2014 के 150 वें स्थान से सुधारकर 63 कर लिया। संक्षेप में मोदीनोमिक्स 1.0 ने कुछ अल्पावधि के संभावित दुष्परिणामों के साथ अप्रत्याशित मैक्रो-इकोनॉमिक ताकत व स्थायित्व दिया।

बजट 20-21 से क्या मिला?: चौकस व विवेकशील अर्थव्यवस्था और मध्यम अवधि का वित्तीय सुदृढ़ीकरण। यह मोदीनोमिक्स 2.0 के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला पहला बजट था। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता को देखते हुए अस्थायी मंदी के मुद्दे का समाधान करेगा। मोदी सरकार की बजट प्रक्रियाओं में जो सबसे बड़ा अंतर दिखा है, वह है चिदंबरम की तरह तथाकथित बिग बैंग बजट का मोह त्यागना, क्योंकि इसने अंत में लोगों को पीड़ा ही दी है। मोदी सरकार ने बजट को वर्ष में एक बार घोषणाओं का मौका न बनाकर, मजबूत गवर्नेंस व कई वर्षों तक चलने वाले आर्थिक रोडमैप का वाहक बनाया है। बजट अब देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताते हैं। जबकि ग्रोथ व विकास के लिए नीतिगत कदम इससे अलग कर दिए गए हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर उठाया जाता है। बजट में नेशनल इंफ्रा पाइप लाइन के लिए अगले पांच वर्षों में 100 लाख खर्च करने, 9000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने और 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया गया है। नेशनल टेक्सटाइल मिशन व कस्टम शुल्क में सुधार टेक्सटाइल उद्योग को नए अवसर देगा।

वित्तीय सेक्टर का विस्तार : पब्लिक सेक्टर के बैंक अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए कैपिटल मार्केट में जाएंगे। एलआईसी को आईपीओ के जरिये बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की तरलीकरण की समस्या के हल को एक नई वित्तीय खिड़की बनेगी। बजट में हाल के महीनों में सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स, उत्पादन क्षेत्र को इंसेंटिव, एफडीआई, विनिवेश व पब्लिक सेक्टर बैंक क्रेडिट को लेकर किए गए फैसलों की भी छाप है, जिसकी घरेलू व विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए जरूरत थी। ग्रोथ आगामी तिमाही में सकारात्मक हो जाएगी और जल्द ही 5.5 से 6.0 के स्तर को छू सकती है। एलआईसी का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इससे देश की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी में गवर्नेंस व पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और इससे यह विश्व स्तर की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी में बदल सकती है। लेकिन, एक सफल आईपीओ लाना चुनौतीपूर्ण काम है। सरकार को इसकी प्रक्रिया के प्रबंधन की योजना सावधानी से बनानी चाहिए और जल्द से जल्द इसे शुरू करना चाहिए। हाल ही में सऊदी अरब की आरामको के आईपीओ से साफ है कि अगर सही से मैनेज न किया जाए तो यह प्रक्रिया कितनी जटिल और कठिन है। एक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय को करीब ढाई लाख रुपए (3500 डॉलर) की ओर ले जाएगी।